भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2930
उत्तर देने की तारीख 10 जुलाई, 2019

मोबाइल टावर लगाने में धोखाधड़ी

2930. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मोबाइल टावर लगाने में धोखाधड़ी की कोई शिकायत मिली है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) जी, हां। सरकार को मोबाइल टावर लगाने में धोखाधड़ी की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग को मोबाइल टावर लगाने में धोखाधड़ी से संबंधित प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध 'क'** पर दिया गया है।

(ग) सरकार ने इन धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए विभिन्न पहल की है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

I. किसी मोबाइल टावर की स्थापना दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) अथवा अवसंरचना सेवा प्रदाता (आईपी-1) द्वारा अपनी लाइसेंसिंग/पंजीकरण शर्तों के अनुसार की जाती है। टीएसपी और आईपी-1 की सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट यानि www.dot.gov.in पर उपलब्ध है। टावर लगाने में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए, कोई भी व्यक्ति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से टीएसपी/आईपी-1 की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। यदि कोई कंपनी/अभिकरण/व्यक्ति मोबाइल टावर को वास्तविक रूप से स्थापित करने से पहले अग्रिम राशि अथवा पंजीकरण शुल्क या किसी भी प्रकार के भुगतान की मांग करता है तो इसका सत्यापन संबंधित कंपनी से किया जाए।

II. यदि कोई व्यक्ति अथवा कंपनी 1) मोबाइल टावर लगाने के नाम पर अग्रिम राशि प्राप्त करने 2) दूरसंचार विभाग का नाम/प्रतीक चिन्ह सिफारिश अथवा राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग करने जैसे कार्यकलापों में धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है तो उन पर लागू विधि के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के धोखाधड़ी कार्यकलापों की जानकारी होती है तो उसे ऐसी घटना के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय दूरसंचार प्रर्वतन, संसाधन और निगरानी (टर्म) प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग की क्षेत्र इकाई से संपर्क किया जा सकता है जिनकी संपर्क संख्या दूरसंचार विभाग की वेबसाइट यानि www.dot.gov.in पर उपलब्ध है।

III. आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, दूरसंचार विभाग समय-समय पर मोबाइल टावर लगाने में इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए प्रिंट मीडिया में सलाह जारी करता है। ऐसी सलाह को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।

अनुबंध-क

लोक सभा में 'मोबाइल टावर लगाने में धोखाधड़ी' के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री एस.ज्ञानतिरावियम द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2019 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2930 के भाग 'ख' के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार प्राप्त शिकायतें

रिपोर्ट की अवधि: 01/01/2019 से 30/06/2019

श्रेणी: टावर के मुद्दे: धोखाधड़ी/जालसाजी

राज्य का नाम	आगे लाया गया	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त	उक्त अवधि के दौरान लंबित	उक्त अवधि के दौरान निपटान
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	1	0	1
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	0	1	0	1
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	2	0	2
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	4	0	4
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	1	0	1
हरियाणा	0	6	0	6
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	1	0	1
कर्नाटक	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	1	0	2
महाराष्ट्र	0	2	0	2
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	2	0	2
पुडुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0
राजस्थान	0	1	0	1
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	4	1	4
तेलंगाना	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1	5	1	5
उत्तराखंड	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	1	0	1
कुल	**3**	**32**	**2**	**33**

राज्य-वार प्राप्त शिकायतें

दिनांक:04/07/2019

रिपोर्ट की अवधि: 01/01/2018 से 31/12/2018

श्रेणी: टावर के मुद्दे: धोखाधड़ी/जालसाजी

राज्य का नाम	आगे लाया गया	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त	उक्त अवधि के दौरान लंबित	उक्त अवधि के दौरान निपटान
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	4	0	4
बिहार	0	5	0	5
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	0	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	4	0	4
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	1	0	1
हरियाणा	0	4	0	4
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	1	0	1
कर्नाटक	0	2	0	2
केरल	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	1	1
महाराष्ट्र	0	3	0	3
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	2	0	2
पुडुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0
राजस्थान	0	1	0	1
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	4	1	3
तेलंगाना	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	15	1	14
उत्तराखंड	1	0	0	1
पश्चिम बंगाल	0	3	0	3
कुल	**2**	**51**	**3**	**50**

राज्य-वार प्राप्त शिकायतें

रिपोर्ट की अवधि: 01/01/2017 से 31/12/2017

श्रेणी: टावर के मुद्दे: धोखाधड़ी/जालसाजी

राज्य का नाम	आगे लाया गया	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त	उक्त अवधि के दौरान लंबित	उक्त अवधि के दौरान निपटान
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	1	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	2	0	2
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	1	0	1
महाराष्ट्र	0	3	0	3
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	1	0	1
राजस्थान	0	1	0	1
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	0	0
तेलंगाना	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	3	0	3
उत्तराखंड	0	1	1	0
पश्चिम बंगाल	0	2	0	2
कुल	**0**	**15**	**2**	**13**

******